जापानी प्रधानमंत्री आबे को नया जनादेश: उनके मंत्रिमंडल के समक्ष मुद्दों और चुनौतियों का आंकलन

*डॉ. शमशाद ए खान**

प्रस्तावना

दिसंबर 2014 में संपन्न आकस्मिक चुनाव में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) और उसके गठबंधन साथी, द न्यू कोमेटो को भारी जीत मिली है। दोनों दलों ने मिलकर जापानी डायट के निचले सदन में दो तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया है। चुनाव परिणामों को प्रधानमंत्री आबे और उनकी नीतियों को भारी समर्थन के रूप में आंका जा रहा हैं, क्योंकि उन्होंने इस चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन का नेतृत्व करते हुए उसे एक और शानदार जीत दिलाई। खुद प्रधानमंत्री आबे ने इस जीत को आबेनॉमिक्स के नाम से प्रसिद्ध अपनी आर्थिक पुनरुद्धार की नीति को साकार करने के लिए नए सिरे से जनता से मिला जनादेश माना। इसके अतिरिक्त, उनकी अपनी प्राथमिकताओं में अन्य विभिन्न गंभीर मुद्दे हैं, जैसेकि जापान की सुरक्षा सुदृढ़ करना; चीन तथा दक्षिण कोरिया समेत पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को पटरी पर लाना और विभिन्न घरेलू नीतियों को लागू करना। इस मुद्दा सार में उन कारकों की पड़ताल की गई है जिसने आबे को इस आकस्मिक चुनाव की घोषणा करने के लिए बाध्य किया और उन कुछ प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया है जिसका सामना आबे मंत्रिमंडल को निकट भविष्य में करना पड़ सकता है।

2014 का आकस्मिक चुनाव: आबे ने जनता के अनुमोदन के लिए आबेनॉमिक्स प्रस्तुत किया

जापान की अर्थव्यवस्था में लगातार दो तिमाहियों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज किए जाने और अर्थव्यवस्था के पुनः मंदी के दौर में चले जाने के कारण प्रधानमंत्री आबे को अर्थव्यवस्था ठीक से नहीं संभालने पर चहुंमुखी आलोचना का सामना करना पड़ा। उनके विरोधियों ने जापान को एक और आर्थिक मंदी की ओर धकेलने के लिए आबेनॉमिक्स के रूप में प्रसिद्ध उनकी आर्थिक नीतियों को दोषी ठहराया। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री आबे को पूरा विश्वास था कि आबेनॉमिक्स जापान के आर्थिक पुनरुत्थान का "एकमात्र रास्ता" है। उन्होंने 14

दिसंबर, 2014 के आकस्मिक चुनाव को आबेनॉमिक्स की अपनी नीति के लिए नए सिरे से जनादेश प्राप्त करने का नाम दिया; एक ऐसी नीति जो बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रोत्साहन, ज्यादा आक्रामक मौद्रिक राहत, और जापान की प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से जापानी अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार चाहती है। हालांकि आलोचकों को लगता है कि आबे ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) और प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए इस आकस्मिक चुनाव का आह्वान किया।[1] उनके मन में दो रणनीतियाँ थीं (क) विपक्षी दलों को अपना आधार मजबूत करने के लिए पर्याप्त समय न देना, और (ख) पार्टी के भीतर (मिलने वाली) राजनीतिक चुनौती से बचना। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के तीन प्रमुख गुट हैं और वे अन्ततः प्रधानमंत्री पद हासिल करने हेतु पार्टी के अंदर अध्यक्ष पद हथियाने के लिए प्रतिस्पर्द्धा करते रहते हैं।

जापान ने एक अद्वितीय उदाहरण बनाए रखा है; सत्तारूढ़ दल/गठबंधन का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री बनता है। वर्ष 2015 में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के भीतर अध्यक्ष पद का एक और चुनाव होना था और अगले लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) अध्यक्ष चुनावों में आबे को अध्यक्ष पद से बेदखल करने के लिए उनकी कम होती सार्वजनिक स्वीकार्यता दर को उनके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा उद्धृत किया जा सकता था। अब चूंकि आबे ने पार्टी को एक व्यापक जीत दिलाई है, इसलिए आबे दावा कर सकते है कि उन्हें एक मजबूत जनादेश मिला है और वे जापान का नेतृत्व करने हेतु पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। चुनावों के परिणाम ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के अगले अध्यक्ष के चुनाव के दौरान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के अध्यक्ष के रूप में उनके पुनः निर्वाचित होने और चार और वर्ष के लिए देश का नेतृत्व करने की उनकी संभावनाएं बढ़ा दी हैं।[2]

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आबे की स्वीकार्यता दर हाल ही में लिए गए उनके कुछ निर्णयों के कारण कम होनी प्रारंभ हो गई थी, जैसे – रक्षा बलों को सामूहिक आत्म-रक्षा की अनुमति देने हेतु संविधान की फिर से व्याख्या और सूचना को वर्गीकृत करने हेतु गुप्त सूचना संरक्षण कानून नामक एक कानून बनाना – जिन को, जैसाकि विभिन्न जनमत सर्वेक्षणों ने संकेत दिया है, पर्याप्त संख्या में जापानियों द्वारा समर्थन प्राप्त नहीं था। जापानी मीडिया सर्वेक्षणों के अनुसार, जब प्रधानमंत्री आबे ने दिसंबर 2012 में अपना प्रशासन शुरू किया तब उनकी स्वीकार्यता दर 65 प्रतिशत थी और अस्वीकार्यता दर केवल 26 प्रतिशत थी। इन आकस्मिक चुनावों की घोषणा से एक सप्ताह पहले, आबे के मंत्रिमंडल की सार्वजनिक स्वीकार्यता दर घटकर 49 प्रतिशत रह गई थी, जबकि अस्वीकार्यता दर ने 42 प्रतिशत (के आंकड़े) को छू लिया था।[3] जापानी प्रधानमंत्री के अस्तित्व और उसकी सार्वजनिक स्वीकार्यता दर के बीच एक अद्वितीय सह-संबंध होता है। विगत में कई प्रधानमंत्रियों ने जनता द्वारा अपने नेतृत्व की अनुमोदन की निम्न दर का हवाला देते हुए या

तो इस्तीफा दे दिया या पार्टी के भीतर ही अपने उत्तराधिकारी के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। वर्ष 2009 में, जब विपक्षी जापान डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपीजे) ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) से सत्ता छीनी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री तारो असो के मंत्रिमंडल का अनुमोदन दर गिरकर मात्र नौ प्रतिशत रह गया था। लेकिन उन्होंने आकस्मिक चुनाव कराने और डायट को अपना कार्यकाल पूरा करने देने के पार्टी के सुझाव को खारिज कर दिया। इससे विपक्षी दलों को अपनी ठोस रणनीति बनाने और जनता के मोहभंग को अपने पक्ष में भुनाने का पर्याप्त समय मिल गया। हालांकि, इतनी जल्दी सत्ता अगले नेतृत्व के हाथ में सौंपने की भावना आबे के मन में नहीं थी। प्रधानमंत्री की हैसियत से उन्होंने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके आकस्मिक चुनाव की घोषणा कर दी, जैसा कि उनके कई पूर्ववर्तियों ने अतीत में किया था। अब, आकस्मिक चुनावों में निर्वाचित होने के बाद, उन्हें न केवल जनता से एक नया जनादेश मिल गया है, बल्कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) पर उनकी पकड़ भी मजबूत हो गई है।

आकस्मिक चुनावों के दौरान चुनावी मुद्दे

यह दिलचस्प था कि आबे ने चुनाव अभियान में आबेनॉमिक्स पर ध्यान केंद्रित किया तथा संवैधानिक संशोधन, परमाणु रिएक्टरों को पुन: आरंभ करने और ओकिनावा में अमेरिकी अड्डों की अवस्थिति जैसे विभाजनकारी मुद्दों को दरकिनार कर दिया। मीडिया द्वारा किए गए जनमत सर्वेक्षण में बताया गया कि इन मुद्दों पर अधिकांश जापानी जनता लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) का समर्थन नहीं करती है। अभियान के अंतिम चरण में, आबे ने आबेनॉमिक्स की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों जैसे रोजगार और मजदूरी (के क्षेत्र में) सुधार को उजागर किया और कहा कि देश के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए "यही एकमात्र रास्ता है।" जापान डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपीजे) सहित विपक्षी दलों ने अपने चुनाव अभियान में समाज में आर्थिक विषमता बढ़ाने के लिए आबे की आलोचना यह कहकर की कि आबेनॉमिक्स ने अमीरों और बड़े निर्यातकों की सहायता की है। जापानी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने चुनाव अभियान में आबेनॉमिक्स की आलोचना की और जापान को परमाणु मुक्त बनाने का शपथ लिया और मतदाताओं से यह भी वायदा किया कि संसद में अपनी शक्ति बढ़ाकर वह संविधान की पुन: व्याख्या करने के मंत्रिमंडल के निर्णय को बदलने की मांग करेंगे जिसके द्वारा जापानी रक्षा बलों को और अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं।[4] लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) की गठबंधन सहयोगी, द न्यू कोमेटो ने भी सामूहिक आत्मरक्षा के मुद्दे पर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) से अपने मतभेदों को उजागर किया। उसने कहा कि वह "जापान को एक शांतिपूर्ण देश के पथ का अनुसरण करने की दिशा में ले जाएगा और इसे अन्य देशों की धरती पर बल प्रयोग करने की अनुमति कभी नहीं देगा।"[5] चूंकि चुनाव से पहले अर्थव्यवस्था वापस मंदी की ओर जाने लगी, इसलिए आबे प्रशासन ने उपभोग कर में वृद्धि करने की तैयार योजना को अप्रैल 2017 तक स्थगित कर दिया। कम

मजदूरी पाने वाले उपभोक्ताओं पर उपभोग कर में एक बार फिर से बढ़ोत्तरी के प्रभाव को कम करने हेतु न्यू कोमिटो ने मतदाताओं से कतिपय आवश्यक दैनिक वस्तुओं पर उपभोग कर की वृद्धि में कटौती करने का वायदा किया। लेकिन, दैनिक आवश्यक वस्तुओं को उपभोग कर की वृद्धि से बाहर रखा जाए या नहीं - इस मुद्दे पर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। यह उल्लेखनीय है कि जापान ने अपने सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में ऋण को कम करने तथा पिछले दो दशकों से जारी अपस्फीति से जापान को बाहर निकालने के लिए पिछले वर्ष उपभोग कर पाँच प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत कर दिया था।

चूंकि विपक्ष कमजोर ही बना रहा और कोई गठबंधन बना पाने के साथ-साथ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) का कोई स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करने में विफल रहा, इसलिए आकस्मिक चुनाव का आह्वान करने का आबे का दांव सफल सिद्ध हुआ। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ने जापानी डायट के 475 सदस्यों वाले निचले सदन की 291 सीटें जीत लीं और इसके सहयोगी न्यू कोमेंटो ने 35 सीटों पर जीत दर्ज की। इस प्रकार, सत्तारूढ़ गठबंधन ने निचले सदन में दो तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया। भले ही विपक्षी दलों के बहुमत वाला ऊपरी सदन आबे की नीतियों से सहमत नहीं हो, पर डायट (निचले सदन) में दो तिहाई बहुमत से आबे को विभिन्न कानूनों को पारित करने में मदद मिलेगी। यदि यह साधारण बहुमत होता तो निचले सदन द्वारा पारित विधेयकों पर ऊपरी सदन के पास रोड़े अटकाने की पर्याप्त शक्ति थी। यदि ऊपरी सदन को निचले सदन द्वारा पारित विधेयक पर कुछ आपत्तियां होती हैं तो निचला सदन विधेयकों को दो तिहाई बहुमत से पारित कर उन आपत्तियों को रद्द कर सकता है।

यह दिलचस्प है कि मुख्य विपक्षी दल, जापान डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपीजे) ने इस चुनाव में 11 सीटें प्राप्त कीं और डायट के निचले सदन में इसकी कुल संख्या 73 तक पहुँच गयी है। लेकिन इसने ये सीटें अन्य कट्टर दक्षिणपंथी छोटे दलों को तबाह करने की कीमत पर हासिल की है। ओसाका के पूर्व गवर्नर टोरु होशिमोटो के नेतृत्व वाली जापान इन्नोवेशन पार्टी डायट में 41 सीटें लेकर दूसरा (बड़ा) विपक्षी दल बन गया जबकि जापान कम्युनिस्ट पार्टी 21 सीटें जीतकर तीसरा (बड़ा) विपक्षी दल बन गया है और इसे इन चुनावों में बड़ा लाभ मिला है क्योंकि 8 सीटों के स्थान पर 21 सीटें जीतकर इसकी शक्ति में वृद्धि हुई है। यह उल्लेखनीय है कि इस आम चुनाव में (मात्र) 52 फीसदी मतदान दर्ज किया गया, जो 1947 के बाद का सबसे कम मतदान है। जहां कुछ विश्लेषकों का मानना है कि लोग मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचे क्योंकि उनके पास पर्याप्त विकल्प नहीं थे, वहीं एक अन्य वर्ग का मानना था कि इसका कारण जापान के विभिन्न हिस्सों में खराब मौसम और भारी बर्फबारी थी।

आबे सरकार के समक्ष चुनौतियां

आबेनॉमिक्स: जापान के आर्थिक पुनरुत्थान के वादे को पूरा करना

इस चुनाव में कम मतदान के चाहे जो भी कारण रहे हों, आबे विजेता बन चुके हैं और उन्होंने पार्टी के साथ-साथ प्रशासन पर भी अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। लेकिन उनके समक्ष अभी भी देश को दीर्घ अपस्फीति और आर्थिक मंदी से बाहर लाने की चुनौतियां हैं। वे आश्वस्त हैं कि लोगों ने आबेनॉमिक्स को लागू करने के लिए एक नया जनादेश दिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी चुनौतियां दिन-प्रतिदिन बड़ी होती जा रही हैं। नवीकृत आंकड़ों से पता चलता है कि लगातार पिछली दो तिमाहियों के दौरान अर्थव्यवस्था में वार्षिक आधार पर 1.9 प्रतिशत की कमी हुई है न कि 1.6 प्रतिशत की, जैसा कि पहले बताया गया था। अपने सकल घरेलू उत्पाद पर जापान का ऋण 226 प्रतिशत है और अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुमान है कि इस राजकोषीय वर्ष के अंत तक यह बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 245 प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन जापान के लिए यह राहत की बात है कि सरकार का यह ऋण अपनी ही जनता का बकाया है और चूंकि यह ऋण आंतरिक है, इसलिए यह देश को किसी वित्तीय संकट की ओर नहीं ढकेलेगा, जैसा कि यूनान में देखा गया है, जिसका ऋण अपने सकल घरेलू उत्पाद का 175 प्रतिशत है। गत वर्ष बैंक ऑफ जापान (बीओजे) के साथ परामर्श करके आबे प्रशासन ने विकास-चक्र की एक योजना तैयार की है जिसमें वस्तुओं की बढ़ती कीमतें कंपनियों को अधिक लाभ देंगी जिससे बेहतर वेतन, अधिक खर्च और उच्च कीमतों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो अंततः अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगा।[6] यह योजना दोहरी रणनीति प्राप्त करने के उद्देश्य से लाई गई थी; दो प्रतिशत मुद्रास्फीति (दर) प्राप्त करना और अतिरिक्त कर लगाकर सरकार पर कर्ज कम करना। इसके पश्चात, आबे प्रशासन ने अप्रैल 2014 में सरकारी राजस्व बढ़ाने और ऋण कम करने के लिए, जो बढ़कर एक करोड़ शंख येन (1000 खरब येन) अथवा लगभग 8.5 खरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया, उपभोग कर में और अधिक वृद्धि कर दी। लेकिन अतिरिक्त उपभोग कर लगाने से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है और उपभोक्ता घरों और कारों जैसे बड़ी मदों वाली वस्तुएं खरीदने से विमुख हो रहे हैं, क्योंकि अतिरिक्त तीन प्रतिशत कर के कारण इनकी कीमतें बढ़ गई हैं। उपभोग कर में वृद्धि से बसों और मेट्रो के किराए सहित कीमतों में वृद्धि हो गई है, जो कम आय वाले परिवारों की जेब पर भी भारी पड़ी है। जापान ने उपभोग कर में अगले वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि करने की योजना बनाई है, लेकिन सरकार ने अर्थव्यवस्था के संकुचन के बाद अर्थव्यवस्था में ठहराव तथा मंदी के डर से इसे वर्ष 2017 तक स्थगित करने का निर्णय लिया। रुझान दर्शाता है कि दो प्रतिशत मुद्रास्फीति होने की संभावना नहीं है, जितना कि बैंक ऑफ जापान (बीओजे) ने जापान को संकुचन से बाहर निकालने के लिए आवश्यक माना है। आबे सरकार अतिरिक्त उपभोग कर के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए नियोक्ताओं से बातचीत कर रही है कि वे अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करें।

पिछले कुछ महीनों के दौरान, सरकार ने विभिन्न प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की है और बैंक ऑफ

जापान (बीओजे) ने अपने परिणामात्मक उपायों के तहत बाजार में पैसे जारी किए हैं। इससे येन कमजोर हुआ है और जिससे व्यापारियों, विशेषकर बड़े निर्यातकों को मदद मिली है। लेकिन कमजोर येन, जो अमरीकी डॉलर के मुकाबले 121 (अंकों) तक गिर गया है (आबे के सत्ता में आने के बाद से पहली बार डॉलर के मुकाबले 41 प्रतिशत का मूल्यह्रास), का व्यापारियों, विशेषकर विदेशों से माल का आयात करने वालों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वे या तो मूल्य में वृद्धि करके खरीददारों पर बोझ डाल रहे हैं या उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए अपने लाभ की सीमा (मार्जिन) बहुत ही कम रख रहे हैं। विश्व स्तर पर तेल की कीमतों में आई कमी ने जापान को थोड़ी राहत दी है, जो बड़ी मात्रा में तेल का आयात करता है, लेकिन यदि येन और गिरता है, तो यह जापानी उपभोक्ताओं पर ज्यादा भारी पड़ेगा।

लेकिन, आबे दृढ़ जान पड़ते हैं क्योंकि वे नियोक्ताओं पर जोर देते रहे हैं कि वे कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दें, ताकि उन्हें उपभोग कर में वृद्धि का एहसास न हो तथा अर्थव्यवस्था का प्रवाह कायम रहे। 27 दिसंबर को आबे मंत्रिमंडल ने गतिहीन ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में जान डालने के लिए 3.5 खरब येन के एक और प्रोत्साहक पैकेज को अनुमोदित कर दिया। आबेनॉमिक्स का तीसरा तीर, अवसंरचनात्मक सुधार, उन्हें अभी चलाना है। यह देखना अभी शेष है कि कब वे अवसंरचनात्मक सुधार की नीति प्रारंभ करते हैं, जिसे प्रारंभ करने का आग्रह विभिन्न अर्थशास्त्री करते रहे हैं।[7]

कृषि क्षेत्र में सुधार: वफादारों द्वारा प्रतिरोध

कृषि सुधार आबे प्रशासन के प्रमुख एजेंडा में से एक है। तथापि, यह आबे के लिए एक दुष्कर कार्य सिद्ध हो सकता है और उन्हें कृषि सहकारी निकायों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के परंपरागत वोट बैंकों में से एक रहे हैं। अतीत में, जब जापान डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपीजे) शासन के दौरान नाओटो कान प्रशासन ने प्रशांत-पार भागीदारी करार, जो उन वस्तुओं पर सीमा-शुल्क न लगाने की नीति को बढ़ावा देता है जिनका भागीदार देशों के बीच व्यापार किया जाएगा, में शामिल होने के अपने इरादे की घोषणा की थी, तब बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतर आए थे। विरोधों के बावजूद जापान डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपीजे) सरकार अपने इरादे से टस से मस नहीं हुई और उसने यह तर्क दिया कि प्रशुल्क समाप्त कर देने से जापान की निर्यातोन्मुख अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी और इससे कृषि क्षेत्र के सुधारों सहित घरेलू सुधार को गति मिलेगी। दूसरी ओर, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ने तर्क दिया था कि जापान अपने हितों की रक्षा करेगा और यदि इन हितों की रक्षा नहीं होती है तो यह (जापान) टीपीपी में शामिल नहीं भी हो सकता है। यह इसी शपथ के साथ वर्ष 2012 के चुनावों में उतरी और कृषि निगमों से समर्थन जुटाने में सफल रही। हालांकि, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ने यू-टर्न ले लिया और प्रधानमंत्री आबे ने मार्च 2013 में टीपीपी में शामिल होने के निर्णय की आधिकारिक घोषणा कर दी।

किसान समुदाय के अपने वफादार मतदाताओं को आश्वस्त करने के लिए आबे ने घोषणा की कि जापान चावल, जौ, चीनी, दुग्ध उत्पाद तथा गाय और सुअर के मांस सहित पांच प्रमुख उत्पादों के लिए शून्य प्रशुल्क उन्मूलन में अपवाद प्रदान करने हेतु टीपीपी सहयोगियों से वार्ता करेगा। हालांकि, कृषि निकाय इससे आश्वस्त नहीं हुए और उन्होंने यह तर्क देते हुए टोकियो में प्रदर्शन किया कि प्रशुल्क हटाने से सस्ते आयातित कृषि उत्पाद की बहुतायत से कृषि क्षेत्र में नुकसान होगा।[8] वर्ष 2014 आकस्मिक चुनावों के दौरान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) जापान के प्रशान्त पार भागीदारी (टीपीपी) (में शामिल होने के मुद्दे) को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने से बचती रही, जिसका उद्देश्य अपने परंपरागत मतदाताओं को परेशान न करना था। एलडीपी के स्थानीय प्रभाग ने किसान समुदाय को लुभाने के प्रयास में अपने चुनावी दौर में वायदा किया कि वे कतिपय कृषि उत्पादों पर से प्रशुल्क हटाने की अनुमति नहीं देंगे जो कि टीपीपी वार्ताओं में एक प्रमुख मांग है।[9] हालांकि चुनावों के बाद आबे प्रशासन एक ओर मई 2015 तक टीपीपी में शामिल होने[10] के लिए वार्ताओं को पूरा करने हेतु प्रतिबद्ध जान पड़ता है, वहीं दूसरी ओर इसने कृषि क्षेत्र में सुधारों[11] को प्रारंभ करने हेतु एक योजना की घोषणा की है। आबे प्रशासन ने जिस मूल योजना का अनावरण किया है, उसमें किसानों के खेतों को एकीकृत करने, इस क्षेत्र में व्यापार निगमों के प्रवेश का विस्तार करने और उच्चतर मूल्य वाले उत्पादों[12] के विकास के माध्यम से किसानों की प्रतियोगी भावना को बढ़ाने का आह्वान किया गया है। तथापि आलोचकों का मानना है कि इस नीति से जापान के कृषि क्षेत्र का पुनरूद्धार होने की संभावना नहीं है। जापान टाइम्स ने अपने स्तंभ में तर्क दिया है:

> जापान की कृषि बड़ी संख्या में लघु-स्तर की कृषि एककों और वृद्ध होते किसानों वाली है। अनेक कृषि समुदाय पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित हैं। यह विचारणीय है कि क्या सरकार की मूल योजना ऐसी परिस्थितियों में लागू हो सकेगी और क्या यह वास्तव में इन कृषि समुदायों के पुनरूद्धार में सहायक होगी?[13]

आबे की कृषि क्षेत्र में सुधार की सफलता कृषि निकायों के सहयोग पर निर्भर करेगी। यह इस बात पर भी निर्भर करेगी कि अंतत: जब जापान टीपीपी में शामिल हो जाएगा तो क्या वे कृषि समुदायों के हितों की रक्षा करने में सफल हो पाएंगे?

चीन और दक्षिण कोरिया के साथ वार्ताएं पुन: बहाल करना

कूटनीतिक स्तर पर जापानी प्रधानमंत्री आबे के समक्ष एक दुष्कर कार्य है - दक्षिण कोरिया तथा चीन के साथ संबंधों को वापस पटरी पर लाना। इस आकस्मिक चुनाव से पहले आबे ने अपनी 'विश्व-यात्रा' कूटनीति के भाग के रूप में 50 से अधिक राष्ट्रों का दौरा किया था और वे ऐसा करने वाले पहले जापानी प्रधानमंत्री

हैं। तथापि दक्षिण कोरिया और चीन के साथ संबंध अस्पष्ट बने रहे जो कि उनके बीच इतिहास तथा भू-भाग के मुद्दों पर मतभेदों के कारण था और जापान तथा चीन और जापान तथा दक्षिण कोरिया के नेतृत्व के बीच राजनीतिक वार्ताएं स्थगित रहीं। इसका प्रभाव उस त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन पर पड़ा, जिसका प्रारंभ इन तीन क्षेत्रीय शक्तियों ने अपने राजनीतिक तथा आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए किया था। वे बीजिंग में एपेक शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त समय में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक बैठक करने में सफल रहे थे और वे चीन के साथ आगे वार्ताएं करने के इच्छुक हैं। आकस्मिक चुनाव के पश्चात प्रधानमंत्री का कार्यकाल फिर से प्रारंभ करने के बाद अपने भाषण में आबे ने दक्षिण कोरिया और चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने की आशा व्यक्त की। हालांकि चीनी पक्ष ने बताया है कि चीन-जापान संबंध में कोई भी सुधार मुख्य रूप से आबे सरकार की कार्यवाहियों पर टिका है। वर्ष 2015 द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति की 70वीं वर्षगांठ है। चीन युद्ध वर्षगांठ पर आबे के रूख की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है।[14] इस बीच आबे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की सत्तरवीं वर्षगांठ पर एक नया वक्तव्य जारी करने की योजना बना रहे हैं।[15] वर्ष 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री तोमिची मुरायामा ने युद्ध की समाप्ति की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर जापानी सरकार की ओर से एक वक्तव्य जारी किया था। बाद में, वर्ष 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जुनीचीरो कोईजुमी ने द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक वक्तव्य जारी किया। दोनों ही वक्तव्यों में पूर्वी एशिया तथा इससे आगे के क्षेत्र में अपने साम्राज्यवादी विस्तार के दौरान जापान की कार्यवाहियों तथा आक्रमकता पर खेद व्यक्त किया गया। हालांकि आबे ने इशारा किया था कि उनका वक्तव्य "भविष्योन्मुखी" होगा। इसके कारण समीक्षाकारों को विश्वास हो गया कि उनके वक्तव्य में विश्वयुद्ध के दौरान जापान की आक्रमकता को नजरअंदाज किए जाने की संभावना है। जापान के पमुख दैनिक, योमियुरी शिंबुन ने यह कहते हुए सरकार को सुझाव दिया कि वह "अपना भविष्योन्मुखी संदेश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी बताएं" कि "जापान को अपने युद्ध मृतकों का शोक किस प्रकार मनाना चाहिए, यह उसका घरेलू मामला है। दूसरे देशों को इसके बारे में और जापान के आंतरिक मामलों के संबंध में शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है।"[16] तथापि, अशाही शिंबुन का मानना है कि यदि आबे अपने नए वक्तव्य में इतिहास को प्रदर्शित नहीं करते तो यह परेशानी का सबब बन सकता है। यह लिखता है कि उन्हें (प्रधानमंत्री आबे) का बार-बार जोर देना कि वे एक "भविष्योन्मुखी" संदेश देंगे, परेशान कर रहा है। इसका तर्क हैः

> “कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि एक "भविष्योन्मुखी" दृष्टिकोण अपनाना गलत है। फिर भी यदि जापान अपने अतीत का गंभीरता से सामना किए बिना भविष्य के बारे में बातें करना प्रारंभ करता है तो वे देश जिन्होंने युद्ध के दौरान जापान के व्यवहार को झेला है, वे यह सोचना प्रारंभ कर देंगे कि क्या जापानी कह रहे हैं "चलिए, अतीत को भूल जाएं।”[17]

जापान में आलोचकों का यह भी मानना है कि चीन और दक्षिण कोरिया द्वारा नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करना तय है, यदि आबे के वक्तव्य में ऐतिहासिक दोहराव का संकेत देते हुए कड़ी भाषा का प्रयोग होगा। वे आबे को अपना वक्तव्य तैयार करते समय बाहर के विशेषज्ञों, विशेषकर चीन और दक्षिण कोरिया के जानकार विशेषज्ञों से परामर्श लेने की सलाह दे रहे हैं।[18] एक जापानी कूटनीतिक विशेषज्ञ का मानना है कि "यदि वक्तव्य में अतीत को नए सिरे से लिखने का प्रयास करते हुए स्व-दोषरहित भाषा निहित रहती है, तो यह दक्षिण कोरिया और चीन द्वारा जापान विरोधी प्रचार अभियान चलाने के लिए एकदम सही बहाना प्रदान करेगा।"[19] पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुदृढ़ करना आबे के एजेंडा की सर्वोपरि प्राथमिकताओं में से एक है, लेकिन यह बहुत कुछ इसपर निर्भर करेगा कि वे इतिहास पर अपना वक्तव्य कैसे तैयार करते हैं। घरेलू मतदाताओं से प्राप्त इन सुझावों के बाद कि वक्तव्य में किसी भी संशोधन से पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, आबे ने संकेत दिया है कि युद्ध की 70वीं वर्षगांठ पर उनके वक्तव्य में "शोक" व्यक्त किया जाएगा।[20] यह गौरतलब है कि जापान तथा दक्षिण कोरिया और जापान तथा चीन के बीच एक मजबूत आर्थिक परस्पर-निर्भरता के बावजूद इन दोनों पड़ोसियों के साथ जापान के कूटनीतिक संबंध में ऐतिहासिक मुद्दा एक बड़ी परेशानी बन गया है।

जापानी सुरक्षा सुदृढ़ करना और अमरीका-जापान सुरक्षा संबंध का पुनरूद्धार करना

चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री आबे ने जापानी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है, जिनमें शामिल हैं - कोनिनावा में अमरीकी अड्डे की पुनःअवस्थिति, जापानी रक्षा बलों को सामूहिक स्वरक्षा का प्रयोग करने की अनुमति देने हेतु संविधान की पुनः व्याख्या का संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ इन क्षेत्रों में बदलती सुरक्षा स्थिति की वास्तविकताओं को प्रदर्शित करने हेतु 1995 अमरीका-जापान रक्षा दिशानिर्देशों में संशोधन करना। विशाल बहुमत से जीतने के बावजूद, आबे के समक्ष अपने सुरक्षा एजेंडा को साकार करने में घरेलू बाधाएं सामने आ रही हैं। नए अमरीका-जापान रक्षा दिशानिर्देश को अप्रैल से पहले अंतिम स्वरूप दिए जाने की संभावना है, जब आबे का राष्ट्रपति ओबामा से मिलने के लिए अमेरिका की यात्रा पर जाना निर्धारित है। वाशिंगटन दौरे से पहले आबे प्रशासन जापान में मौजूद अमरीकी बलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए कुछ अमरीकी मरीन को फुतेनामा अ डे से हटाकर ओकिनावा के होनोको में अवस्थित करने के लिए 2006-अमरीका-जापान करार को लागू करना चाहता है, लेकिन आबे प्रशासन को ओकिनावा में स्थानीय सरकार से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। आम चुनाव के कुछ सप्ताह पहले, ताकशाही ओनागा ने अपने प्रांत में अमरीकी मरीन कोर हवाई अड्डा को स्थानांतरित करने की टोकियो की योजना को रोक देने की शपथ लेकर गवर्नर स्तरीय चुनाव जीता था। राष्ट्रव्यापी भारी समर्थन के बावजूद, एलडीपी आम चुनाव के दौरान सभी चारो सीटों पर हार गया और जिन्होंने स्थानांतरण का विरोध किया था, वे विजयी होकर उभरे। जापानी मीडिया का एक वर्ग आबे से ओकिनावा की जनभावना का सम्मान करने का आग्रह कर रहा है।[21]

इसी प्रकार, शासक गुटों के भीतर मतभेद जापानी टुकड़ियों द्वारा सामूहिक स्वरक्षा का प्रयोग करने (के मुद्दे) पर सामने आ गए हैं। पिछले वर्ष मंत्रिमंडल ने संविधान की पुनःव्याख्या की है और अपनी टुकड़ियों को कुछ आपात स्थितियों में सामूहिक स्वरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी है। अब, जहां वर्तमान मंत्रिमंडल संविधान की पुनर्व्याख्या के अपने निर्णय के बारे में जापानी डायट से अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने हेतु बिल तैयार कर रहा है, वहीं न्यू कोमितो, जो कि शासी गठबंधन में कनिष्ठ भागीदार है, वह सरकार से जापान के आसपास के क्षेत्रों तक आपात स्थितियों में सामूहिक स्वरक्षा के अधिकार के प्रयोग को सीमित करने की मांग कर रहा है। लेकिन लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) अपने बलों द्वारा सामूहिक स्वरक्षा के अधिकार के प्रयोग पर भौगोलिक प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती है। इन घरेलू चुनौतियों और गठबंधन के भीतर के मतभेद के कारण आबे अपनी सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करेंगे।[22]

निष्कर्ष

पिछली बार जब लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ने "जापान को वापस लिया" ('जापान को वापस लो' वर्ष 2012 के आम चुनाव के दौरान आबे का नारा था), तो यह मुख्य रूप से इसलिए हुआ क्यों कि (जनता का) एक बड़ा वर्ग, जिस प्रकार से तत्कालीन सत्ताधारी जापान डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपीजे) जापान पर शासन कर रही थी, उससे खुश नहीं था और आबे लोगों के जापान डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपीजे) से विकर्षण लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के पक्ष में भुनाने में सफल रहे। हालांकि इस बार उन्होंने जापानी अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार के लिए आबेनोमिक्स के नाम पर जनता से नए सिरे से जनादेश मांगा है, लेकिन उन्होंने अपने प्रशासन की प्राथमिकता पर अनेक एजेंडों को ऊपर रखा है। जनता का एक बड़ा वर्ग जापानी अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार हेतु अपने चुनावी वायदे पर केन्द्रित रहने की उनसे अपेक्षा रखता है और वे उनकी सुरक्षा नीति का आवश्यक रूप से समर्थन नहीं करते।[23] इस संबंध में आबे और उनके प्रशासन से उन्हें बड़ी आशाएं हैं। यह केवल समय ही बताएगा कि क्या आबे लोगों की आकांक्षाओं पर खरे उतर पाएंगे।

*_*डॉ. शमशाद ए खान विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं। हाल ही में इन्होंने जापान इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स (जेआईआईए), टोकियो, जापान में अपनी विजिटिंग अनुसंधान अध्येतावृत्ति पूरी की है। इस लेख में वयक्त किए गए कुछ विचार जापान दौरे के उनके व्यक्तिगत पर्यावलोकन पर आधारित हैं। लेखक द्वारा व्यक्त विचार उनके अपने हैं और ये जेआईआईए अथवा आईसीडब्ल्यूए के विचारों को प्रदर्शित नहीं करते।_*

समाप्ति नोट:

[1] जीरो यामागुची, "शिन्जो आबे का राजनीतिक एजेंडा", *द जापान टाइम्स*, 27 नवम्बर 2014

[2] जापानी डायट के निचले सदन का कार्यकाल चार वर्ष का है।

3 "सर्वेक्षण पाता है कि आबे मंत्रिमंडल का समर्थन दर 6.8 अंक नीचे गिरकर 48.1 प्रतिशत रह गया है।" *द जापान टाइम्स / क्योदो समाचार,* 19 अक्तूबर, 2014.

[4] "जेसीपी के प्रमुख कहते हैं कि आबेनॉमिक्स विफल हो गया" *द जापान टाइम्स*, 27 नवम्बर 2014.

[5] "कोमेइटो ने बिक्री कर समाप्त करने संबंधी कार्रवाई करने का वायदा किया", *द जापान टाइम्स*, 28 नवम्बर 2014.

[6] बीओजे अपस्फीति से जुझ रहा है, हारूहीको कुरोडा, बैंक ऑफ जापान के गवर्नर से साक्षात्कार, *एनएचके टीवी*, 2 दिसम्बर, 2014 http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/news/onbusiness/2014122202.html पर ऑनलाइन उपलब्ध।

[7] ताकामित्सु सावा, "सुर्खियों में आबेनॉमिक्स", *द जापान टाइम्स*, 9 दिसंबर, 2014.

[8] 'जापान के टीपीपी वार्ता में भाग लेने पर टोकियो में विरोध प्रदर्शन के लिए रैली निकाली गई', *द जापान टाइम्स*, 13 मार्च, 2013.

[9] "लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) अभियान संदेश शहर व देश की ओर मुड़ा", *द जापान टाइम्स*, 4 दिसंबर, 2014.

[10] "जापान, अमरीका ने कार्यात्मक स्तर पर टीपीपी वार्ता पुन: प्रारंभ की, *द जापान टाइम्स*, फरवरी 3, 2015.

[11] "आबे के कृषि सहकारिता सुधार,"(सम्पादकीय), *द जापान टाइम्स*, फरवरी 3, 2015.

[12] पूर्वोक्त।

[13] पूर्वोक्त।

[14] "युद्ध की वर्षगांठ पर चीन को आबे के रुख का इंतजार", *द जापान टाइम्स*, 21 दिसंबर, 2014.

[15] "सरकार मार्च से द्वितीय विश्व युद्ध की 70वीं वर्षगांठ पर वक्तव्य (तैयार करने) पर काम करना प्रारंभ कर सकती है", *द जापान टाइम्स*, 4 जनवरी, 2015.

[16] "द्वितीय विश्वयुद्ध के 70 वर्ष बाद, अब शांति, इतिहास पर भविष्योन्मुख वार्ता करने का समय है" (सम्पादकीय), *द योमिउरी शिम्बुन*, 3 जनवरी, 2015.

[17] "जापान को युद्ध के लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए" (सम्पादकीय), *द असाही शिम्बुन*, 3 जनवरी, 2015.

[18] "युद्ध की 70वीं वर्षगांठ के लिए आबे पर सभी की नजर", *द जापान टाइम्स*, 2 जनवरी, 2015.

[19] पूर्वोक्त।

[20] "आबे का कहना है कि आत्मसमर्पण की 70वीं वर्षगांठ पर वक्तव्य में पश्चाताप व्यक्त करेंगे" *द जापान टाइम्स*, 6 जनवरी, 2015.

[21] "टोकियो ने ओकिनावा के गवर्नर के (बयान को) बचकाना, उलटा असर वाला बताकर फटकार लगाई, *द असाही शिम्बुन*, 31 दिसंबर, 2014.

[22] "लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) और कोमेटो में संभारतंत्रीय/रसद सहायता कानून पर मतभेद" *द योमियुरी शिम्बुन*, 31 दिसंबर, 2014.

23 "चुनावी जीत का अर्थ आबे की नीतियों का सम्पूर्ण अनुमोदन नहीं" (सम्पादकीय) *द मेनीची डेली/दैनिक*,, 15 दिसंबर, 2014.